Staff employed in BICP

1710. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of staff employed in the Bureau of Industrial Costs and Prices;

(b) what are the names of officers and consultants who are in BICP for more than three years and since when;

(c) what was the total expenditure incurred on them during 1989-90 and 1990-91;

(d) what are the total number of reports sent by BICP during the last two years, year-wise; and on what items;

(e) what were the recommendations on each item and when was each recommendation sent;

(f) whether it is a fact that the work being done by this organisation does not commensurate with the expenses incurred by Government; and

(g) if so, the steps being taken to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) One Hundred and Sixty (160).

(b) and (c) Information is given at Annexures I and II.

[*See* Appendix CLIX Annexure No. 47 and 48]

(d) Information relating to total number of reports year-wise, item-wise is given in Annexure III.

[*See* Appendix CLIX, Annexure No. 49].

(e) The recommendations contained in the reports of the BICP are treated as confidential. However, month of submission is indicated against each report at Annexure III.

(f) No, Sir.

(g) Does not arise.

पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई विकास परियोजनाओं की संख्या

1711 सरदार आर्जुन सिंह दरोड़ : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में कतिपय विकास योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था यदि हां, तो उनकी वर्ष-वार संख्या कितनी कितनी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ परियोजनायें पिछले कई वर्षों से पहले ही निर्माणाधीन थीं, यदि हां, तो उनमें से कितनी परियोजनायें पूरी हो गई हैं;

(ग) कितनी परियोजना पिछड़ रही हैं; और

(घ) विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हो जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां । कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 43 परियोजनायें वर्ष 1989-90 में तथा 26 परियोजनायें वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय क्षेत्र में ली गई थीं ।

(ख) जी, हां । कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली वर्ष 1989-90 के दौरान 38 परियोजनायें और वर्ष 1990-91 दौरान 70 परियोजनायें केन्द्रीय क्षेत्र में पूरी की गई ।

(ग) और (घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार, 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार